

अमेरिका ने स्टील पर टैरिफ किया दोगुना, भारत बोला—सीमित रहेगा असर

4 जून से लागू होगा 50% आयात शुल्क, वैश्विक बाजार में कीमतों के तेज उछाल की आशंका

नई दिल्ली। अमेरिका ने वैश्विक व्यापार जगत को झटका देते हुए स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर सीमा शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यह नया शुल्क 4 जून 2025 से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला ट्रेड एक्सपैशन एक्ट, 1962 की धारा 232 के तहत लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अमेरिका में स्टील की कीमतों में और तेजी आएगी और इसका असर वैश्विक बाजार पर भी देखने को मिलेगा हालांकि भारत सरकार ने इस निर्णय को लेकर फिलहाल गंभीर चिंता नहीं जताई है। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमार

स्वामी ने कहा कि अमेरिका की टैरिफ नीति में लगातार अस्थिरता देखी जा रही है और अभी के फैसले से भारत के स्टील निर्यात पर बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें दो-तीन महीने इंतजार करना चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। गौरतलब है कि भारत ने बीते वित्त वर्ष में अमेरिका को लगभग 4.56 अरब डॉलर मूल्य का स्टील और एल्यूमीनियम निर्यात किया था, जिसमें से 3.1 अरब डॉलर सिर्फ स्टील का निर्यात था। अमेरिका में इस समय स्टील की कीमत करीब 984 डॉलर प्रति टन है, जो नए टैरिफ के लागू होने के बाद 1180 डॉलर प्रति टन तक पहुंच सकती है। इसके विपरीत यूरोप में



स्टील की कीमत 690 डॉलर और चीन में मात्र 392 डॉलर प्रति टन है, जबकि भारत में यह 500 से 550 डॉलर प्रति टन के बीच है। इस कारण अमेरिका में भारतीय स्टील की मांग बनी हुई थी, लेकिन शुल्क बढ़ने से लागत में बढ़ोतरी भारतीय स्टील को कम प्रतिस्पर्धी बना सकती है। भारत सरकार इस मामले पर कड़ी निगरानी रख रही है और अन्य देशों की संरक्षणवादी नीतियों के मद्देनजर व्यापक विमर्श कर रही है, ताकि घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सके। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के इस फैसले से न केवल भारत को चुनौती मिलेगी, बल्कि

अमेरिका के ऑटोमोबाइल और निर्माण क्षेत्र पर भी लागत का बोझ बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस स्थिति में WTO का रुख अपनाना चाहिए, जैसा कि उसने 2018 में किया था। इस पूरी स्थिति में भारत के पास चुनौती के साथ-साथ नए अवसर भी हैं। अगर रणनीतिक रूप से सही कदम उठाए जाएं तो भारत अपने स्टील निर्यात को वैश्विक बाजारों में मोड़कर इस नुकसान की भरपाई कर सकता है। सरकार को व्यापारिक नीतियों में लचीलापन दिखाते हुए घरेलू उद्योग को संरक्षण देना होगा और वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति मजबूती से रखनी होगी।

महंगाई से जूझते कारोबारियों को राहत

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 24 सस्ता, 1 जून से लागू नई दरें



रेस्टोरेंट-दुबों का संचालन हुआ थोड़ा आसान, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव

नई दिल्ली। अमेरिका ने वैश्विक व्यापार जगत को झटका देते हुए स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर सीमा शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यह नया शुल्क 4 जून 2025 से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला ट्रेड एक्सपैशन एक्ट, 1962 की धारा 232 के तहत लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अमेरिका में स्टील की कीमतों में और तेजी आएगी और इसका असर वैश्विक बाजार पर भी देखने को मिलेगा हालांकि भारत सरकार ने इस निर्णय को लेकर फिलहाल गंभीर चिंता नहीं जताई है। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि अमेरिका की टैरिफ नीति में लगातार अस्थिरता देखी जा रही है और अभी के फैसले से भारत के स्टील निर्यात पर बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने यह

भी कहा कि हमें दो-तीन महीने इंतजार करना चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। गौरतलब है कि भारत ने बीते वित्त वर्ष में अमेरिका को लगभग 4.56 अरब डॉलर मूल्य का स्टील और एल्यूमीनियम निर्यात किया था, जिसमें से 3.1 अरब डॉलर सिर्फ स्टील का निर्यात था। अमेरिका में इस समय स्टील की कीमत करीब 984 डॉलर प्रति टन है, जो नए टैरिफ के लागू होने के बाद 1180 डॉलर प्रति टन तक पहुंच सकती है। इसके विपरीत यूरोप में स्टील की कीमत 690 डॉलर और चीन में मात्र 392 डॉलर प्रति टन है, जबकि भारत में यह 500 से 550 डॉलर प्रति टन के बीच है। इस कारण अमेरिका में भारतीय स्टील की मांग बनी हुई थी, लेकिन शुल्क बढ़ने से लागत में बढ़ोतरी भारतीय स्टील को कम प्रतिस्पर्धी बना सकती है। भारत सरकार इस मामले पर कड़ी निगरानी रख रही है और अन्य देशों की

संरक्षणवादी नीतियों के मद्देनजर व्यापक विमर्श कर रही है, ताकि घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सके। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के इस फैसले से न केवल भारत को चुनौती मिलेगी, बल्कि अमेरिका के ऑटोमोबाइल और निर्माण क्षेत्र पर भी लागत का बोझ बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस स्थिति में WTO का रुख अपनाना चाहिए, जैसा कि उसने 2018 में किया था। इस पूरी स्थिति में भारत के पास चुनौती के साथ-साथ नए अवसर भी हैं। अगर रणनीतिक रूप से सही कदम उठाए जाएं तो भारत अपने स्टील निर्यात को वैश्विक बाजारों में मोड़कर इस नुकसान की भरपाई कर सकता है। सरकार को व्यापारिक नीतियों में लचीलापन दिखाते हुए घरेलू उद्योग को संरक्षण देना होगा और वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति मजबूती से रखनी होगी।

सिंह ने मोदीजी से पूछा: क्या 'दो चुटकी सिंदूर' का इतना राजनीतिक महत्व है?

भाजपा के 'घर-घर सिंदूर' अभियान पर तीखा हमला



नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा पर 'दो चुटकी सिंदूर' को लेकर तीखा हमला बोला है। सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह भारतीय महिलाओं की भावनाओं का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए घर-घर जाकर सिंदूर बांटने का अभियान चला रही है। इसे

उन्होंने एक सस्ता राजनीतिक स्टंट करार दिया और इसे 'एक राष्ट्र, एक पति' योजना तक जोड़कर व्यंग्य किया। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सिंदूर महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सम्मान और खुशहाली के प्रतीक के रूप में लगाया जाता है, जो गर्व और गरिमा का भाव रखता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल

किया कि क्या उन्होंने दो चुटकी सिंदूर के गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व को समझा है। सिंह ने कहा, 'यह सिर्फ राजनीतिक नौटंकी नहीं, बल्कि महिलाओं का अपमान है। भारतीय महिलाएं अपने पति के लिए सिंदूर लगाएंगी, किसी राजनीतिक नेता के लिए नहीं। भाजपा कब तक इस परंपरा का दुरुपयोग करती रहेगी?' उन्होंने केंद्र सरकार की सुरक्षा नीतियों पर भी निशाना साधा, बताया कि पहलगाम हमले के आतंकियों का पता नहीं चल पाया और पीओके अभी तक भारत को वापस नहीं मिला। सिंह ने कहा कि भारतीय सेना की ताकत होने के बावजूद सरकार ने युद्धविराम का विकल्प चुना जबकि भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर सिंदूर बांटने में लगे हैं। भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि ऐसी कोई योजना या अभियान पार्टी की ओर से नहीं चलाया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस की केरल इकाई ने भी इस मुद्दे पर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। संजय सिंह की इस टिप्पणी से राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराओं के इस्तेमाल को लेकर बहस फिर गर्मा गई है।

'आतंक का फन उठेगा तो कुचल देंगे': पीएम मोदी ने नेपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में दी सख्त चेतावनी

इंदौर मेट्रो और दतिया-सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन

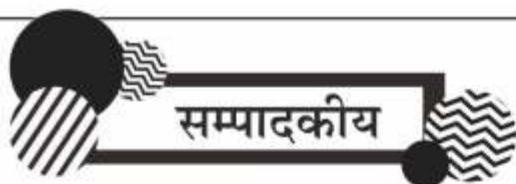
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित 'लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन' में आतंकवादियों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने हमारे समाज और संस्कृति पर हमला किया है, लेकिन अगर आतंक का फन उठेगा तो उसे पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के

सबसे बड़े और सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक बताया, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को समाप्त किया गया। प्रधानमंत्री ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन इच्छाशक्ति और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने महिलाओं की भूमिका को विकास की घुरी बताते हुए कहा कि हमारी



सरकार 'Women Led Development' के विजन पर काम कर रही है, और महिलाओं ने देश की सुरक्षा और विकास में अहम योगदान दिया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। साथ ही दतिया और सतना एयरपोर्ट का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। इससे अलावा, उज्जैन में आगामी

सिंहस्थ महापर्व 2028 के लिए घाट निर्माण और जल संरक्षण से जुड़े बड़े परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। 1,271 नए अटल ग्राम सुशासन भवनों के लिए 483 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी की गई। प्रधानमंत्री के इस दौरे ने नारी शक्ति को सम्मानित करते हुए मध्य प्रदेश के समग्र विकास को नई ऊर्जा दी है।



दोतरफा खतरे के बीच तेज और सटीक रक्षा तैयारियों की आवश्यकता

भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ पहले से कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी हो चुकी हैं। एक ओर पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, तो दूसरी ओर चीन अपनी सैन्य क्षमता और रणनीतिक विस्तार के जरिए भारत की सीमाओं पर लगातार दबाव बना रहा है। ऐसे में जब भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह रक्षा परियोजनाओं में हो रही देरी पर सवाल उठाते हैं, तो यह सिर्फ सैन्य नेतृत्व की चिंता नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक चेतावनी है। यह चिंता केवल कागजों पर बनी योजनाओं और हवाई घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई है, जिसमें वायुसेना को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया लगातार विलंब का शिकार हो रही है। भारतीय वायुसेना की भूमिका अब सीमित नहीं रही, बल्कि यह किसी भी युद्ध या ऑपरेशन में निर्णायक शक्ति बन चुकी है। इसका ताजा उदाहरण हाल में हुआ ऑपरेशन 'सिंदूर' है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को एयरस्ट्राइक के जरिए नष्ट कर अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ हमारी सैन्य क्षमता को दुनिया के सामने रखा, बल्कि यह भी दिखाया कि आज की लड़ाइयों में वायु शक्ति कितनी निर्णायक हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी वायुसेना के पास ऐसे ऑपरेशनों को दोहराने और लंबे समय तक लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन और तकनीक हैं? वायुसेना प्रमुख का बयान इसी सवाल को सामने लाता है। भारत को अपनी वायुसेना के लिए कम से कम 42.5 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की जरूरत है, जबकि वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ही हैं। यानी हमारे पास लगभग 200 से अधिक लड़ाकू विमान कम हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, खासकर तब जब दोनों सीमाओं पर तनाव लगातार बना हुआ है। HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) को तेजस मार्क-1A की डिलीवरी करनी थी, जो कि एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है और भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम माना जाता है। लेकिन डिलीवरी में देरी हो रही है, जिससे वायुसेना की तैयारी पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तेजस विमान, तकनीकी रूप से अत्याधुनिक है, लेकिन निर्माण प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें और संसाधनों की कमी इसकी गति को बाधित कर रही हैं। वहीं, दूसरी ओर हमारे विरोधी लगातार अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन पहले ही अपनी सेना के आधुनिकीकरण में कई सालों से अग्रसर है। अब खबरें हैं कि चीन अपने जे-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जो पांचवीं पीढ़ी का उन्नत लड़ाकू विमान है, पाकिस्तान को देने की योजना बना रहा है। यह विमान रडार पर न पकड़ में आने वाली तकनीक से लैस है और यदि पाकिस्तान को यह विमान मिलते हैं, तो भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली के सामने एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इस समय पाकिस्तान तुर्किये के ड्रोन और चीन के हथियारों का प्रयोग कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि दोनों देशों की सैन्य साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। सरकार ने भारत में भी पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण को मंजूरी दे दी है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 साल तक का समय लग सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तब तक भारत अपने विरोधियों की तकनीकी बढ़त को सहता रहेगा? या फिर उसे अभी से तेजी से काम करके इस अंतर को पाटना होगा? हालांकि एक सकारात्मक पहलु यह है कि भारत ने 'मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। 2023-24 में देश ने 1.27 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन किया, और 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रक्षा निर्यात भी हुआ। भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण बेच रहा है, और पिछले एक दशक में यह वृद्धि लगभग 30 गुना हुई है। यह निश्चित रूप से एक उपलब्धि है, लेकिन जब तक हमारी सेनाएं इन उत्पादों से पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं होती, तब तक इन आंकड़ों का वास्तविक प्रभाव हमारी रक्षा शक्ति पर नहीं पड़ता। सवाल अब यह नहीं है कि भारत रक्षा उत्पादन कर पा रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या यह उत्पादन समय पर और जरूरत के अनुसार हो पा रहा है? जब वायुसेना प्रमुख खुद यह कह रहे हैं कि योजनाएं कागजों पर अटकती हैं, तो यह दर्शाता है कि नीति और अमल के बीच एक गंभीर खाई मौजूद है। इस खाई को पाटने के लिए जरूरी है कि रक्षा परियोजनाओं को 'फास्ट ट्रैक' मोड में लाया जाए, निर्माण की हर प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाए, और समयसीमा का सख्ती से पालन हो। भारत के लिए यह समय अब केवल रणनीति बनाने का नहीं, बल्कि रणनीति के क्रियान्वयन में तेजी लाने का है। चीन की तरह भारत को भी अपने सैन्य आधुनिकीकरण के लक्ष्य तय कर उन्हें समय पर पूरा करना होगा। यह केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सरकार, उद्योग और नागरिक समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने में सहयोग करें। निष्कर्षतः, जब सीमाओं पर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, और विरोधी देश अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो रहे हैं, तब भारत के पास देरी का विकल्प नहीं बचता। वायुसेना की ताकत अब केवल सुरक्षा का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास और संप्रभुता की पहली दीवार बन चुकी है। इसे मजबूत करने में हर सेकंड कीमती है। सरकार को चाहिए कि वह वायुसेना प्रमुख की चेतावनी को गंभीरता से ले और हर परियोजना को मिशन मोड में पूरा करे, ताकि भारत हर परिस्थिति में अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम रहे।

युवा पीढ़ी को जोड़ेंगे संस्कृति से

सिन्धु ज्योति सेवा समिति अजमेर व सिन्धु सेवा समिति किशनगढ़ ने किया एकजुट प्रयास का ऐलान, वरदान फिल्म से समाज में जागरूकता की नई लहर

अजमेर। सिन्धी भाषा, साहित्य, गीत-संगीत, लोक कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु अजमेर की सिन्धु ज्योति सेवा समिति और किशनगढ़ की सिन्धु सेवा समिति अब संयुक्त प्रयास करेंगी। इस उद्देश्य से आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में दोनों समितियों ने मिलकर यह संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सिन्धी फिल्म "वरदान-3" के निर्माता और कंवर फिल्मस के निर्देशक विजय शाहनी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सिन्धी संस्कृति से जोड़े बिना सिन्धुयत को सहेजना संभव नहीं। उन्होंने बताया कि दोनों समितियाँ मिलकर सिन्धी भाषा, लिपि और संस्कृति की जानकारी युवाओं तक पहुँचाने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित करेंगी। इस अवसर पर किशनगढ़ की सिन्धु सेवा समिति द्वारा अजमेर की सिन्धु ज्योति सेवा समिति के प्रमुख पदाधिकारियों का पुष्पमालाओं, शॉल, पूज्य झूलेलाल साहिब के लॉकेट वाली माला और प्रसिद्ध "बनी ठनी" की चित्र भेंट कर विशेष सम्मान किया गया। सम्मान प्राप्त करने वालों में संरक्षक विजय



शाहनी, तेजभान आसवानी, अध्यक्ष मंधाराम भिरयानी, मीडिया प्रभारी रमेश लालवानी और सलाहकार राजेश आनंद प्रमुख रूप से शामिल थे। वयोवृद्ध समाजसेवी तेजभान आसवानी ने अपने उद्बोधन में सिन्धुयत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। वहीं अध्यक्ष मंधाराम भिरयानी ने बताया कि जयपुर रोड स्थित माया मंदिर सिनेमा हॉल में दिखाई जा रही

निःशुल्क फिल्म "वरदान" को दर्शकों का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है, जिसकी एडवांस बुकिंग आठ दिन पहले ही पूर्ण हो गई। कार्यक्रम में किशनगढ़ समिति के विष्णु मंधानी, पिशु भाई मूलानी, गिरधारी अमरवानी, विजय गुरनानी, मुकेश मेघानी, करण मंधानी, रमेश खेनानी, राम भाई नानवानी, नरेश मंगलानी और पंकज अमरवानी ने सिन्धु ज्योति सेवा समिति के पदाधिकारियों

को सम्मानित किया। मीडिया प्रभारी रमेश लालवानी ने बताया कि 23 मई से प्रारंभ हुई निःशुल्क फिल्म "मिठडी अम्मा वरदान" को भी समाज के लोगों द्वारा विशेष सराहना मिल रही है। कार्यक्रम के अंत में गिरधारी अमरवानी ने सिन्धु ज्योति सेवा समिति और माया मंदिर प्रबंधक मुरली भाई हासानी सहित हासानी परिवार का आभार व्यक्त किया, जो वर्षों से समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर: वीरांगनाओं को मिला सम्मान, बच्चों की रैली में गुंजा देशभक्ति का स्वर

प्रेसिडेंसी स्कूल ने वीर शहीदों की स्मृति में किया आयोजन



अजमेर। प्रेसिडेंसी स्कूल, अजमेर द्वारा आयोजित 'ऑपरेशन सिंदूर' कार्यक्रम देशभक्ति और शहीद सम्मान की भावना का सजीव उदाहरण बनकर सामने आया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों और उनके परिवारों को समाज के सम्मुख सम्मानित करना था। इस अवसर पर शहीद शंकर सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा कंवर और शहीद भगचंद गुर्जर की पत्नी श्रीमती माया गुर्जर को विद्यालय की ओर से शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार ने दोनों वीरांगनाओं के त्याग, साहस और धैर्य को नमन करते हुए मंच पर उनका भावपूर्ण स्वागत किया। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक विशाल राष्ट्रप्रेम रैली निकाली, जो लाल मंदिर से प्रारंभ होकर पहाड़िया चौराहे तक गई। रैली में छात्रों ने देशभक्ति के नारों के साथ जनमानस को प्रेरित किया। 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम्' जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। रैली के मार्ग में आमजन ने जल पिलाकर एवं पुष्प वर्षा कर छात्रों का अभिनंदन किया। इस आत्मीय स्वागत से प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों में देशभक्ति की भावना और भी प्रबल

हो उठी। रैली के दौरान छात्रों ने मार्ग में एक भावनात्मक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान और उनके परिवारों की पीड़ा को सजीव रूप में दर्शाया गया। यह प्रस्तुति दर्शकों की आंखें नम कर गई और गहरा प्रभाव छोड़ गई। विद्यालय प्रशासन ने रैली में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए खाद्य किट की व्यवस्था भी की,



जिससे आयोजन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री ए.पी. शर्मा ने कहा, "हमारे देश के वीर जवानों और उनके परिवारों का सम्मान करना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारा नैतिक दायित्व है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम बच्चों में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का विकास करना चाहते हैं।" कार्यक्रम का समापन "देश के लिए जो मिटते हैं, वो अमर कहलाते हैं"—इस प्रेरणास्पद पंक्ति के साथ हुआ। आयोजन में उपस्थित सभी अभिभावकों, नागरिकों और विद्यार्थियों ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से ओत-प्रोत करते हैं।

किशनगढ़ में महिला पतंजलि योग समिति का पुनर्गठन, नई टीम को मिली जिम्मेदारी



किशनगढ़। पतंजलि योग समिति की महिला इकाई का रविवार को आर्य समाज भवन में पुनर्गठन किया गया। जिला प्रभारी सरोज मालू की देखरेख में हुए इस कार्यक्रम में समिति की नवगठित टीम की घोषणा की गई और सभी पदाधिकारियों को पदभार की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में संरक्षिका पद पर कौशल्या अग्रवाल, उषा शारदा, संतोष पारीक और सुमन गोयल को नियुक्त किया गया। महिला प्रभारी (अध्यक्ष) के रूप में सरोज शर्मा को जिम्मेदारी दी गई, जबकि मंजू कुमावत को सह प्रभारी बनाया गया। महामंत्री का दायित्व सरोज मालू को सौंपा गया है। वितीय कार्यों की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष सीमा वाघ्ण्य और सह कोषाध्यक्ष संगीता अग्रवाल को दी गई है। संगठन मंत्री सुमन शर्मा और उनकी सह मंत्री ममता बेनावत होंगी। सोशल मीडिया संचालन की जिम्मेदारी रितु मंधानी

को सौंपी गई है, जबकि अंजू अग्रवाल उनकी सह प्रभारी रहेंगी। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अंजू दोषी को सांस्कृतिक प्रभारी और मधु लखोटिया को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। क्रीड़ा मंत्री के रूप में नेहा अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि युवती प्रभारी की भूमिका अंजली अग्रवाल निभाएंगी। समिति की अन्य सक्रिय कार्यकर्ताओं में अनिता छपरवाल, शशि छपरवाल, राजरानी, पार्वती शर्मा और सुमित्रा शर्मा शामिल हैं, जिन्हें भी सेवा कार्यों के लिए प्रेरित किया गया और शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान महिला योग साधिकाओं के उत्साह और सेवा के प्रति समर्पण ने संगठन के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाया। जिला प्रभारी सरोज मालू ने आशा जताई कि नवगठित समिति किशनगढ़ में योग और सेवा कार्यों को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी।

किशनगढ़ में 2 करोड़ की लागत से सड़कों का सुधार कार्य शुरू

राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत किशनगढ़ में पीडब्ल्यूडी द्वारा दो करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों की मरम्मत और उन्नयन कार्य शुरू किए गए हैं। खिड़की बालाजी मंदिर से अंबेडकर सर्किल तक 400 मीटर सीसी रोड निर्माण के लिए खुदाई कार्य शुरू होगा। इससे पहले कई इलाकों में निर्माण

कार्य पूरा हो चुका है। भाजपा नेता महेंद्र पाटनी ने कामों में देरी और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई और कार्य शीघ्र पूर्ण करने की मांग की। स्थानीय नेताओं और नागरिकों ने भी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को लेकर पीडब्ल्यूडी से कार्रवाई की मांग की।

ऑपरेशन शिल्ड में प्रशासन ने दिखाई चौकसी, मॉक ड्रिल में सेना से लेकर आम नागरिक तक सक्रिय



अजमेर। नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने और आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए शनिवार को अजमेर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार द्वितीय सिविल डिफेंस अभ्यास ऑपरेशन शिल्ड का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में मिलिट्री कंपाउंड पर हवाई हमले की काल्पनिक स्थिति बनाकर शत्रु द्वारा एयर स्ट्राइक का सिमुलेशन किया गया। धमाकों के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में आपातकालीन सायरन बजा, जिससे जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग और सिविल डिफेंस की टीमें तत्पर हो गईं। फायर ब्रिगेड तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और

घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को एंबुलेंस और प्रशासन की गाड़ियों से अस्थायी अस्पताल पहुंचाया गया। इस पूरे अभ्यास का नेतृत्व जिला कलेक्टर लोकबंधु ने किया, जिन्होंने पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी की और सभी विभागों की तत्परता और रिसपॉन्स टाइम का मूल्यांकन किया। लोकबंधु ने पिछले मॉक ड्रिल के अनुभवों के आधार पर इस बार बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। अभ्यास के दौरान सेना भी पूरी तरह सक्रिय रही। सेना के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर ड्रिल को वास्तविकता के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका

निभाई। सिविल डिफेंस ने आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेज और प्रभावी कार्यवाही की, जबकि पुलिस ने घटना स्थल से अस्थायी अस्पताल तक का मार्ग यातायात रहित रखा। रेजिडेंट्स कंपाउंड स्थित बहुमंजिला इमारत में मॉक रेस्क्यू ऑपरेशन भी सफलता पूर्वक किया गया। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, मेडिकल स्टाफ और सिविल डिफेंस कर्मियों ने मिलकर कार्य किया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में परिसर की बार-बार जांच कर पीड़ितों की खोज की गई

और उनके कीमती सामान को सुरक्षित रखा गया। घायलों के स्वास्थ्य में सुधार होने पर उनका सामान संबंधित व्यक्तियों को सुपुर्द किया गया, तथा प्रशासन ने लगातार उनकी सेहत पर नजर रखी। सायरन बजने के साथ ही आम नागरिकों ने भी संयमित प्रतिक्रिया दी। राहगीरों ने तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर रुख किया, जिससे अभ्यास में जन सहभागिता का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला। इस मॉक ड्रिल ने प्रशासन की तत्परता, विभागीय समन्वय और आम जनता की जागरूकता को उजागर किया, जिससे जिले की आपातकालीन तैयारी और मजबूत हुई है।

किशनगढ़ में बालिकाओं के लिए मुफ्त सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण शिविर शुरू



किशनगढ़। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा किशनगढ़ एवं मार्बल सिटी अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन टीकाकरण शिविर का शुभारंभ 31 मई 2025 को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जैन और नगर परिषद किशनगढ़ की आयुक्त सीता वर्मा की उपस्थिति रही। मार्बल सिटी अस्पताल के निदेशक एवं परिषद के वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश मनावत ने बताया कि यह टीकाकरण शिविर प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि टीकाकरण के लिए बालिकाओं के साथ आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लाना आवश्यक है। साथ ही टीकाकरण माता-पिता की सहमति से ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर के कारण प्रतिदिन लगभग 200 महिलाओं की

मृत्यु होती है, इसलिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। पात्र बालिकाओं को इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। मार्बल सिटी अस्पताल के निदेशक प्रदीप पापड़ीवाल और नीरज अजमेरा ने बताया कि टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज के बीच 6 महीने का अंतराल रहेगा। यह टीकाकरण अस्पताल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा ठाकुर की देखरेख में किया जाएगा। सचिव भगवान स्वरूप बाहेली ने जानकारी दी कि आज के शिविर में 42 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। प्रचार प्रसार प्रभारी नंदकिशोर अग्रवाल ने बताया कि शिविर से संबंधित जानकारी के लिए मार्बल सिटी अस्पताल के नंबर 8104 21 4444 एवं 8104 2 15555 और भारत विकास परिषद किशनगढ़ के चिकित्सा प्रकल्प प्रभारी सुभाष जामड के नंबर 98291 59277 पर संपर्क किया जा सकता है। शिविर में मातृशक्ति एवं पुरुष सदस्यों की उत्साहजनक उपस्थिति रही। नगर के गणमान्य नागरिक भी इस अवसर पर मौजूद रहे। शिविर अगले दिन रविवार को भी आयोजित होगा।

खरीफ फसलों के MSP में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, किसानों को मिलेगा लागत से 50% अधिक लाभ



किशनगढ़। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में

वृद्धि को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत किसानों को उनकी लागत पर 50 प्रतिशत से अधिक लाभ मिलना सुनिश्चित किया गया है। MSP में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड के लिए 820 रुपये प्रति विन्टल की गई है। इसके बाद रागी में 596 रुपये, कपास में 589 रुपये और तिल में 579 रुपये प्रति विन्टल की बढ़ोतरी की गई है। अन्य फसलें जिनके MSP में वृद्धि की गई है, उनमें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,

अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, दलहन और तिलहन शामिल हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने इस फैसले को किसानों की समृद्धि के लिए एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कार्यकाल अन्नदाताओं को समर्पित रहा है और लगातार किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत भी किसान सम्मान निधि की स्वीकृति से की थी और तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में भी किसानों को प्राथमिकता दी जा रही

है। चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाएगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होगा। देश जब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब कृषि क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर किशनगढ़ में निकली तिरंगा यात्रा, विप्र फाउंडेशन और जय परशुराम सेना ने किया भव्य स्वागत



मदनगंज-किशनगढ़। भारतीय सेना के साहस और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में किशनगढ़ नगर में रविवार को एक भव्य तिरंगा वाहन यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी, जहां जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा और देशभक्ति नारों से यात्रा का स्वागत किया। इस गौरवमयी

अवसर पर विप्र फाउंडेशन, जय परशुराम सेना, खांडल समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विप्र फाउंडेशन के वेद प्रकाश दाधीच, जय परशुराम सेना के संयोजक रूपेश शर्मा (एडवोकेट), खांडल महिला अध्यक्ष विष्णु देवी सुंदरिया, जय परशुराम सेना महिला अध्यक्ष

लीला पंचारिया ने किया। उपस्थित समाजबंधुओं ने उत्साहपूर्वक आतिशबाजी और पुष्पवर्षा कर देशभक्ति का माहौल बना दिया। इस दौरान राजस्थान ब्राह्मण युवा अध्यक्ष धनराज शर्मा (एडवोकेट) सहित अन्य पदाधिकारियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री का अपर्णा, माला और साफा पहनाकर सम्मानपूर्वक स्वागत

किया। यात्रा के दौरान "भारत माता की जय", "शहीद बीरबल अमर रहें" जैसे गगनभेदी नारों से समूचा वातावरण गूंज उठा। देशभक्ति के रंग में रंगे इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में वेद प्रकाश दाधीच, रूपेश शर्मा (एडवोकेट), रामावतार शर्मा, किशन दाधीच, राधेश्याम रुथला, महेश रिणवा, नव मनोज शर्मा, प्रमोद दाधीच, सुशील दाधीच, आर्यन दाधीच, राम जी शर्मा, राजेंद्र शर्मा, राजेश पंचारिया, विष्णु देवी सुंदरिया, लीला पंचारिया, सुनीता शर्मा, रश्मि शर्मा, जुगल शर्मा, भवर चोटिया, रामकिशोर, चंद्र प्रकाश, सुनील, अनिल, मोना बड़ाडरा, अंबिका बड़ाडरा, सुमन बड़ाडरा, चित्रलेखा, महिमा दाधीच, अनिता, सोनू, सुनीता रुथला, अशोक शर्मा, राजेश नवहाल सहित बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग उपस्थित रहे।

महेश नवमी महोत्सव के तहत माहेश्वरी रक्तदान शिविर में 250 यूनिट रक्त संग्रह



किशनगढ़। महेश नवमी महोत्सव 2025 की श्रृंखला में मंगलवार को श्री माहेश्वरी पंचायत संस्था के तत्वाधान में पंचायत भवन परिसर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 250 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर में समाज के सभी वर्गों का उत्साहपूर्ण सहयोग देखने को मिला। विशेष बात यह रही कि महिलाओं और परिवारों की सामूहिक भागीदारी ने शिविर को सामाजिक एकता और सेवा का सशक्त उदाहरण बना दिया। रक्तदान शिविर का केंद्रीय कृषि मंत्री भगीरथ चौधरी और विधायक विकास चौधरी ने अवलोकन किया और रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। शिविर में पंचायत अध्यक्ष रामनारायण झंवर, मंत्री किशन बंग, उपाध्यक्ष व संयोजक विजय शारदा, सह संयोजक भगवान बाहेली, राजकुमार कासट, ओम तोपनीवाल, मुकुट बिहारी मालपाणी, शिविर प्रभारी अमित सोमानी, मीडिया प्रभारी अनिल लड़ा, नितिन राठी, कोषाध्यक्ष सर्वेश्वर राठी, उपमंत्री अजय काबरा, भवन मंत्री अक्षय तापड़िया, पूर्व मंत्री प्रकाश राठी, जुगल जैथलिया, देवकिनन्दन लखोटिया, दिनेश दरक, नवपुवक मंडल अध्यक्ष दीपक मंत्री, तरुण

मंडल अध्यक्ष विवेक इनाणी, रक्षा झंवर सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी अनिल लड़ा ने बताया कि राधाकृष्ण कॉलोनी निवासी सुरभि राठी ने अपने पति सीए आशीष राठी के साथ अपने जन्मदिन पर रक्तदान कर एक प्रेरक मिसाल पेश की। पूर्व समाज मंत्री प्रकाश राठी के परिवार से पूजा राठी, ममता राठी, दिनेश राठी और सागर राठी ने सामूहिक रूप से रक्तदान किया। राजकुमार लोगड परिवार के राजकुमार, वैभव, विशाल और सलोनी ने भी सहभागिता निभाई। महेश झंवर ने इस अवसर पर अपना 64वां रक्तदान कर समाजसेवा में अपनी सतत भागीदारी दर्ज कराई। रमेश-संगीता मालू, अकिंत-सुरभि आग्नीवाल, अमित-अनिता माहेश्वरी, नरेश-मोनिका सारडा, संतोष-पूजा तोपनीवाल, संदीप-आरती राठी, गजेन्द्र मंत्री और मोनिका-संतोष कालरा ने भी शिविर में रक्तदान किया। प्रथम बार रक्तदान करने वालों में तिषा भांगड़िया, सृष्टि चोडक, राघव बग, नकुल झंवर, लखन राठी, अनुराग सारडा, शिवानी मालू, दिव्या बियाणी, नीलम रानद, हेमंत लड़ा, सीमा कालानी, संगीता लाहोटी, राशि मुंदड़ा, अदिति बांगड़, आंचल और सीधी शामिल रही। शिविर को सफल बनाने में राजकीय यगनारायण चिकित्सालय मदनगंज और राजस्थान ब्लड सेंटर की चिकित्सकीय टीम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

- सम्पादक ओमप्रकाश नाजवानी